भारतीय संविधान : प्रमुख भाग (Indian Constitution: Major Parts)

1) वर्तमान संरचना

- 22 भाग → 25 भाग
- 395 अनुच्छेद → 448 अनुच्छेद
- 8 अनुसूचियाँ → 12 अनुसूचियाँ

2) सबसे लंबा भाग → भाग 5 (संघ) : अनुच्छेद 52 से 151

3) हटाया गया भाग → भाग 7 तथा भाग 9

- भाग 7 : भाग 'ख' (Part B) के राज्य क्षेत्र : अनुच्छेद 238
  - ✓ 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956
- मूल भाग 9 : भाग 'घ' (Part D) के राज्य क्षेत्र : अनुच्छेद 243
  - ✓ 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956

हटाया गया

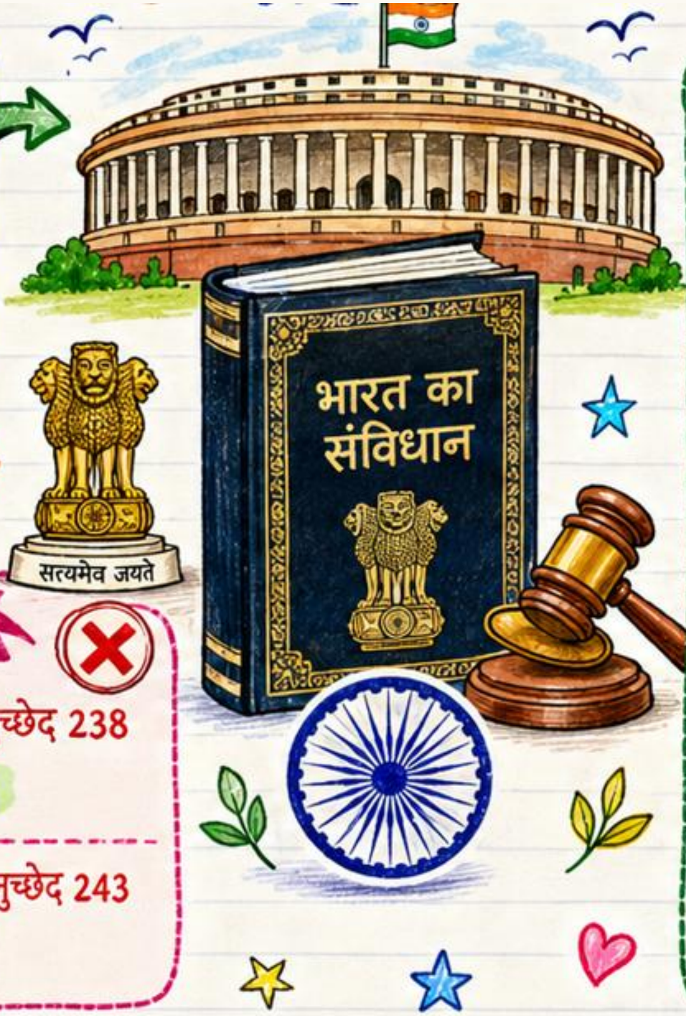

4) जोड़े गए प्रमुख भाग → 05

- ★ भाग 4 (A) : मौलिक कर्तव्य — 42वाँ संशोधन, 1976
- ★ भाग 9 : पंचायतें — 73वाँ संशोधन, 1992
- ★ भाग 9 (A) : नगरपालिकाएँ — 74वाँ संशोधन, 1992
- ★ भाग 9(B) : सहकारी समितियाँ — 97वाँ संशोधन, 2011
- ★ भाग 14 (A) : अधिकरण — 42वाँ संशोधन, 1976

संविधान की संरचना समय के साथ बदलती आवश्यकताओं का जीवंत उदाहरण है !

भारतीय संविधान : प्रमुख भाग (Indian Constitution: Major Parts)

भाग (Part)	विषय (Subject)	संबंधित अनुच्छेद (Related Articles)	महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)
भाग 1 (Part 1)	संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union and its Territory)	1–4	○ अनुच्छेद 1 : India, that is Bharat, shall be a Union of States ○ अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन (Article 3 : Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states)
भाग 2 (Part 2)	नागरिकता (Citizenship)	5–11	○ अनुच्छेद 11 : संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 (Article 11 : Citizenship Act, 1955 enacted by Parliament)
भाग 3 (Part 3)	मूल अधिकार (Fundamental Rights)	12–35	○ 6 मूल अधिकार → "Magna Carta of India"; (6 Fundamental Rights → "Magna Carta of India") ○ **अनुच्छेद 32** → 5 प्रकार की रिट → **"संविधान की आत्मा और हृदय"** (Article 32 → 5 types of Writs → "Soul and Heart of the Constitution")

भाग 4 (Part 4)	नीति-निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)	36–51	○ आयरलैंड से प्रेरित; (Inspired by Ireland) ○ न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, लेकिन शासन के लिए मूलभूत। (Not enforceable by courts, but fundamental to governance)

भाग 4 (A) Part 4 (A)	मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)	51 (A)	○ 42वें संविधान संशोधन, 1976 से जोड़े गए; (Added by the 42nd Constitutional Amendment, 1976) ○ मूल रूप से 10 कर्तव्य, अब 11; (Originally 10 duties, now 11) ○ 86वें संशोधन, 2002 से 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया (11th duty added by the 86th Amendment, 2002)

भाग 5 (Part 5)	संघ (The Union)	52–151	○ राष्ट्रपति / President (52–62) ○ उपराष्ट्रपति / Vice President (63–71) ○ संसद / Parliament (79–122) ○ सर्वोच्च न्यायालय / Supreme Court (124–147) ○ भारत का महान्यायवादी / Attorney General of India (76) ○ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General (148–151)
भाग 6 (Part 6)	राज्य (The States)	152–237	○ राज्यपाल / Governor (153–162) ○ राज्य की मंत्रिपरिषद् / Council of Ministers of the State (163–164) ○ राज्य का महाधिवक्ता / Advocate General of the State (165) ○ राज्य विधानमंडल / State Legislature (168–212) ○ राज्य की विधायी प्रक्रिया / Legislative Process of the State (196-201) ○ उच्च न्यायालय / High Courts (214–231) ○ अधीनस्थ न्यायालय / Subordinate Courts (233–237)

भाग 7 (Part 7)	भाग B राज्य (Part B States)	हटाया गया (Removed)	○ 7वें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा हटाया गया; (Removed by the 7th Constitutional Amendment, 1956)
भाग 8 (Part 8)	केंद्रशासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था (Administration of Union Territories)	239–242	○ पुडुचेरी → अनुच्छेद 239A (Puducherry → Article 239A) ○ दिल्ली → अनुच्छेद 239AA (Delhi → Article 239AA)
भाग 9 (Part 9)	पंचायत (Panchayats)	243–243O	○ 73वाँ संविधान संशोधन, 1992; (73rd Constitutional Amendment, 1992) ○ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई; (11th Schedule added)
भाग 9 (A) (Part 9 (A))	नगरपालिकाएँ (Municipalities)	243P–243ZG	○ 74वाँ संविधान संशोधन, 1992 (74th Constitutional Amendment, 1992) ○ 12वीं अनुसूची जोड़ी गई; (12th Schedule added)

भाग 9 (B) (Part 9 (B)	सहकारी समितियाँ (Co-operative	243ZH–243ZT	○ 97वाँ संविधान संशोधन, 2011 (97th Constitutional Amendment, 2011)
भाग 10 (Part 10)	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (Scheduled and Tribal Areas)	244–244A	○ 5वीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्र; (5th Schedule: Scheduled Areas) ○ 6वीं अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र (6th Schedule: Tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram)
भाग 11 (Part 11)	संघ-राज्य संबंध (Union-State Relations)	245–263	○ 246A → GST से संबंधित विशेष प्रावधान (246A → Special provision related to GST) ○ 248 → अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद के पास (248 → Residuary legislative powers vest with Parliament) ○ 249 → राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद की कानून बनाने की शक्ति (249 → Power of Parliament to legislate on State List in national interest) ○ 250 → आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद की कानून बनाने शक्ति (250 → Power of Parliament to legislate on State List during

भाग 12 (Part 12)	**वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)**	**264–300A**	○ अनुच्छेद 300A → संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि **संवैधानिक/कानूनी अधिकार** है। (Article 300A → Right to Property is no longer a Fundamental Right, but a Constitutional/Legal Right.) ○ मूल रूप से संपत्ति का अधिकार **अनुच्छेद 19(1)(f)** और **अनुच्छेद 31** के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया। (Originally, the right to property was a Fundamental Right under Article 19(1)(f) and Article 31, but it was removed and placed under Article 300A by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978.)

भाग 13 (Part 13)	**व्यापार-वाणिज्य (Trade and Commerce)**	**301–307**	भारत के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता; अनुच्छेद 301 सबसे महत्वपूर्ण। (Freedom of trade within India; Article 301 is the most important.)

भाग 14 (Part 14)	**संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (Services under the Union and States)**	**308–323**	○ अनुच्छेद 312→ अखिल भारतीय सेवाएँ (Article 312 → All India Services) ○ अनुच्छेद 315 से 323 → लोक सेवा आयोग (Articles 315 to 323 → Public Service Commissions)

भाग 14 (A) / Part 14 (A)	**अधिकरण (Tribunals)**	**323A–323B**	42वें संशोधन, 1976 से जोड़ा गया; (Added by the 42nd Amendment, 1976)

भाग 15 (Part 15)	**निर्वाचन (Elections)**	**324–329A**	○ अनुच्छेद 324 → निर्वाचन आयोग (Article 324 → Election Commission of India) ○ अनुच्छेद 326 → वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage)

भाग 16 (Part 16)	**कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (Special Provisions Relating to Certain Classes)**	**330–342A**	○ अनुच्छेद 330 → लोकसभा में SC/ST आरक्षण (Article 330 → Reservation for SC/ST in Lok Sabha) ○ अनुच्छेद 331 → लोकसभा में Anglo-Indian (104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त) / Article 331 → Anglo-Indian representation in Lok Sabha (abolished by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019) ○ अनुच्छेद 332 → विधानसभा में SC/ST आरक्षण (Article 332 → Reservation for SC/ST in State Legislative Assemblies) ○ अनुच्छेद 333 → विधानसभा में Anglo-Indian (104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त) (Article 333 → Anglo-Indian representation in State Legislative Assemblies (abolished by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019)) ○ अनुच्छेद 338 → राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (Article 338 → National Commission for Scheduled Castes) ○ अनुच्छेद 338 (A) → राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (Article 338 (A) → National Commission for Scheduled Tribes) ○ अनुच्छेद 338 (B) → राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (Article 338 (B) → National Commission for Backward Classes)

भाग 17 (Part 17)	राजभाषा (Official Language)	343–351	○ अनुच्छेद 343 → संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी (Article 343 → Official language of the Union is Hindi and script is Devanagari) ○ अनुच्छेद 344 → राजभाषा आयोग और संसदीय समिति (Article 344 → Official Language Commission and Parliamentary Committee)

भाग 18 (Part 18)	आपात उपबंध (Emergency Provisions)	352–360	○ अनुच्छेद 352 → राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह) / Article 352 → National Emergency (war, external or armed rebellion) ○ अनुच्छेद 356 → राष्ट्रपति शासन (राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता) / Article 356 → President's Rule ○ अनुच्छेद 360 → वित्तीय आपातकाल / Article 360 → Financial Emergency

भाग 19 (Part 19)	प्रकीर्ण (Miscellaneous)	361–367	○ अनुच्छेद 361 → राष्ट्रपति/राज्यपाल को संरक्षण (Article 361 → Protection of President/Governor) ○ अनुच्छेद 367 → संविधान की व्याख्या (Article 367 → Interpretation of the Constitution)
भाग 20 (Part 20)	संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)	368	○ अनुच्छेद 368 → संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया (Article 368 → Power and procedure to amend the Constitution)
भाग 21 (Part 21)	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (Temporary, Transitional and Special Provisions)	369–392	○ अनुच्छेद 370 → जम्मू-कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान (Article 370 → Special provisions relating to Jammu & Kashmir) ○ अनुच्छेद 371 → महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान (Article 371 → Special provisions for Maharashtra and Gujarat) ○ अनुच्छेद 371 (A)→ नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान (Article 371 (A) → Special provisions for Nagaland)

भाग 22 (Part 22)	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (Short Title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals)	393–395	○ अनुच्छेद 393 → संविधान का संक्षिप्त नाम (Article 393 → Short title of the Constitution) ○ अनुच्छेद 394 → संविधान का प्रारंभ (Article 394 → Commencement of the Constitution) ○ अनुच्छेद 394 (A) → हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ (Article 394 (A) → Authoritative text in the Hindi language) ○ अनुच्छेद 395 → निरसन (Article 395 → Repeals)

अवधारणा (Concept)	स्रोत (Source)	मूल विचार (Core Idea)	संबंध / अनुच्छेद (Connection / Article)
1. विधि का शासन (Rule of Law)	**ब्रिटेन (ए. वी. डायसी) (Britain (A.V. Dicey)**	सर्वोच्चता: देश में इंसानों का नहीं, बल्कि कानून का राज होगा। (Supremacy: In a country, not men but law shall rule.)	अनुच्छेद 14 का आधार (संविधान का मूल ढांचा) — Basis of Article 14 (Basic Structure of the Constitution)
2. विधि के समक्ष समता (Equality before Law)	**ब्रिटेन (Britain)**	नकारात्मक समता: कानून अंधा है। राजा हो या रंक, कानून की नजर में सब बराबर हैं। (Negative equality: Law is blind. Whether king or pauper, all are equal in the eyes of law.)	अनुच्छेद 14 (विधि के शासन का ही एक हिस्सा) — Article 14 (a part of Rule of Law itself)

3. विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)	अमेरिका (USA)	सकारात्मक समता: कानून अंधा नहीं है। समान लोगों के साथ समान और असमान के साथ अलग व्यवहार (जैसे- आरक्षण)। (Positive equality: Law is not blind. It treats equals equally and unequals differently, e.g., reservation / affirmative action.)	अनुच्छेद 14 (Article 14)
4. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)	जापान (Japan)	प्रक्रियात्मक जांच: न्यायालय केवल यह देखेगा कि कानून बनाने का तरीका/प्रक्रिया सही थी या नहीं। (Procedural check: The court examines only whether the procedure for making the law was correct.)	अनुच्छेद 21 (मूल संविधान में) — Article 21 (in the original Constitution)

5. विधि की उचित प्रक्रिया (Due Process of Law)	**अमेरिका — USA**	तात्विक जांचः न्यायालय देखेगा कि प्रक्रिया के साथ-साथ कानून की नीयत भी न्यायपूर्ण और तार्किक है या नहीं। (Substantive check: The court examines not only the procedure but also whether the law is just, fair, and reasonable.)	अनुच्छेद 21 (मेनका गांधी केस 1978 के बाद) — Article 21 (after Maneka Gandhi case, 1978)

संविधान से हटाए गए महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Significant Articles Removed

1 अनुच्छेद 31 – संपत्ति का अधिकार

क्या था :
मूल संविधान में संपत्ति अर्जित करने, रखने और उसका निपटान करने का अधिकार, **भाग III** के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था।

कैसे हटाया गया :
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार **भाग XII** में **अनुच्छेद 300A** के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। अब यह एक वैधानिक/संवैधानिक अधिकार है, लेकिन **मौलिक अधिकार नहीं** है।

संपत्ति / प्रॉपर्टी

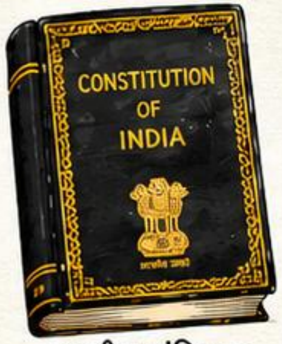

भारतीय संविधान

भाग III (मौलिक अधिकार) → अनुच्छेद 300A

भाग XII (वैधानिक अधिकार)

वर्ष **1978** — 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

2 अनुच्छेद 379 से 391

क्या थे : ये अनुच्छेद स्वतंत्रता के तुरंत बाद आवश्यक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित थे, जैसे अस्थायी संसद और अंतरिम सरकारों का संचालन।

कैसे हटाय गए : 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, **1956** द्वारा इन्हें निरस्त किया गया, क्योंकि **प्रथम आम चुनाव** हो चुके थे और संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं की आवश्यकता समापत हो गई थी।

अस्थायी संसद

→ अंतरिम सरकारें

→

प्रथम आम चुनाव

वर्ष **1956** — 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956

3 अनुच्छेद 329A

क्या था :
1975 में आपातकाल के दौरान 39वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को सामान्य न्यायालयों की समीक्षा से बाहर रखता था।

कैसे हटाया गया :
राज नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराया और बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे औपचारिक रूप से **निरस्त कर दिया गया**।

आपातकाल **1975**

→

प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव

→
राज नारायण मामला (सर्वोच्च न्यायालय ने **असंवैधानिक ठहराया**)

→
सर्वोच्च न्यायालय

वर्ष **1978** — 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

Exam Point: अनुच्छेद **31, 379-391** और **329A** भारतीय संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिंन्हें समय, परिस्थितियों और संवैधानिक संशोधनों के अनुसार हटाया गया।

याद रखें!
- संशोधन = परिवर्तन
- संविधान = जीवंत दस्तावेज ✓

★ Quick Revision Notes ★

Significant Articles Removed from the Constitution

Quick Constitutional Revision Notes

1 Article 31 – Right to Property

What was it?

Originally, the right to acquire, hold, and dispose of property was a Fundamental Right under Part III of the Constitution.

How was it removed?

It was abolished by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978. The Right to Property was shifted to Part XII under Article 300A. It is now a legal / constitutional right, but no longer a Fundamental Right.

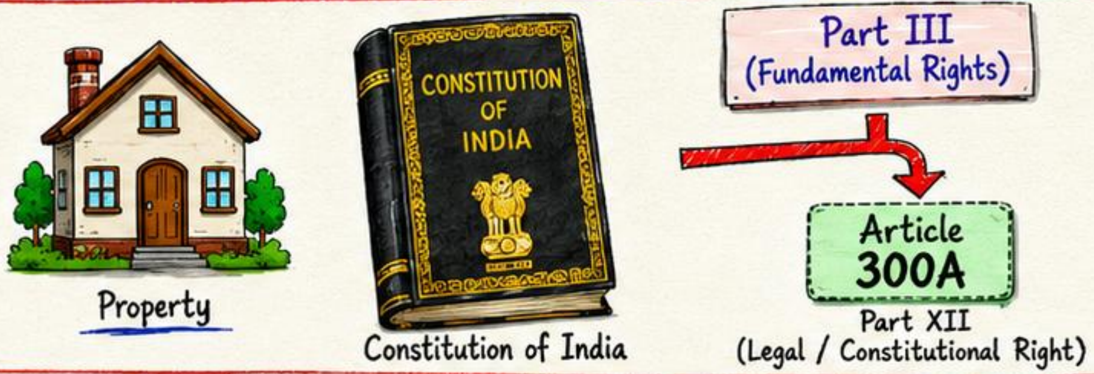

Year **1978**
44th Constitutional Amendment Act, 1978

2 Articles 379 to 391

What were they?

These articles dealt with temporary and transitional provisions needed immediately after independence, such as the functioning of the provisional Parliament and interim governments.

How were they removed?

They were repealed by the 7th Constitutional Amendment Act, 1956, because the first general elections had already been held and the transitional arrangements were no longer needed.

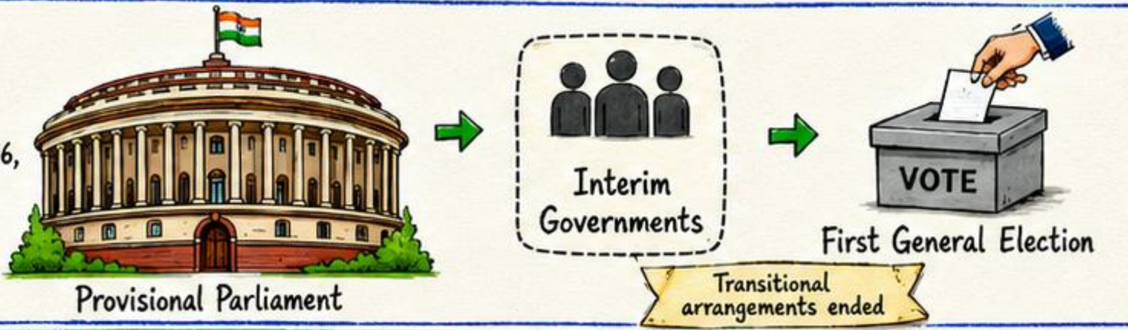

Year **1956**
7th Constitutional Amendment Act, 1956

3 Article 329A

What was it?

Inserted during the Emergency by the 39th Constitutional Amendment in 1975, this article placed the elections of the Prime Minister and the Speaker of the Lok Sabha beyond the scrutiny of ordinary courts.

How was it removed?

In the Raj Narain case, the Supreme Court declared it unconstitutional. It was later formally repealed by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978.

Year **1978**
44th Constitutional Amendment Act, 1978

Exam Point:
Articles 31, 379–391, and 329A are important constitutional provisions that were removed over time due to changing circumstances and constitutional amendments.

Remember!
- Amendment = Change
- Constitution = A living document

Quick Revision Notes

भारत के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक अब एक ही APP पर
SELECTION BATCH 11.0
ADMISSION STARTS
6 AUG
BATCH STARTS
11 AUG
• LIVE CLASSES • COURSE VALIDITY : 2 YEARS
Basic to Advanced
Conceptual Clarity
Pdf Notes & Tests
Live Classes
MATHS
GAGAN SIR
ENGLISH
AMAN SIR
REASONING
VIKRAMJEET SIR
REASONING
BALRAM SIR
GS
VARUN SIR
GS
SHUBHAM SIR
SCIENCE
RADHIKA MA'AAM
UPGRADED
Course Fee : 1999/-
SelectionWay

Whatsapp : 837-394-80-00

SelectionWay
New way of Learning

Call No. 638-897-46-50

GS FOUNDATION 1.0

NCERT निचोड़ BATCH

ADMISSION STARTS **6 AUG** | BATCH STARTS **11 AUG**

- LIVE CLASSES
- COURSE VALIDITY : 2 YEARS

INCLUDES

- Live Classes
- Pdf Notes & 100+ Tests
- Conceptual Clarity
- From Basic to Top Rank

USEFUL FOR

- SSC Exams
- Railway Exams
- ALL Competitive Exams

UPGRADED

Shubham Sir

Course Fee : 499/-

SPECIAL OFFER

Special Discount Only for first 1000 Students | Download Selectionway App